



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 15, 2016/पौष 25, 1937

No. 21]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 15, 2016/ PAUSA 25, 1937

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 22 दिसम्बर, 2015

सं. टीएएमपी/20/2010-केपीटी.-महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा, केपीटी की गांधीधाम नगर भूमि की संरचना-दरों की वैधता, एतत् द्वारा इसके साथ संलग्न आदेश अनुसार बढ़ायी जाती है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/20/2010-केपीटी

कांडला पत्तन न्यास

.....

आवेदक

आदेश

(दिसंबर 2015 के 7 वें दिन पारित)

यह मामला केपीटी की गांधीधाम नगर भूमि की संरचना दरों की वैधता अवधि में बढ़ोत्तरी के लिए कांडला पत्तन न्यास(केपीटी) के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव से संबंधित है।

2. कांडला पत्तन न्यास(केपीटी) की गांधी धाम नगर भूमि के लिए लीज़ किराया इस प्राधिकरण द्वारा 09 अप्रैल, 2012 को संशोधित किया गया था जो 01 जनवरी, 2009 से पिछले प्रभाव से लागू किया गया था। यह लीज़ किराया 5 साल तक के लिए वैध था अर्थात् 31 दिसंबर 2013 तक वैध था। तत्पश्चात इस प्राधिकरण द्वारा केपीटी के गांधीधाम नगर भूमि की मौजूदा दर संरचना की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया है।

3. केपीटी के अनुरोध पर केपीटी की गांधीधाम नगर भूमि के लिए मौजूदा दर-संरचना, पिछली बार इस प्राधिकरण द्वारा आदेश संख्या टीएएमपी/20/2010 -केपीटी दिनांक 13 फरवरी, 2015 के अंतर्गत पिछली वैधता समाप्त होने की तिथि से 30 जून 2015 या केपीटी द्वारा प्रस्तुत प्रशुल्क प्रस्ताव के आधार पर संशोधित किराये की

अधिसूचना अनुसार, जो भी पहले हो बढ़ाया गयी थी। वैधता बढ़ाते समय केपीटी को गांधीधाम नगर भूमि के लिए संरचना दर के संशोधित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव, हर हालत में 31 मार्च 2015 तक प्रस्तुत करने के निदेश दिए गए थे।

4. अब केपीटी ने दिनांक 20 नवम्बर 2015 के पत्र में उल्लेख किया है कि गांधीधाम नगर भूमि के लिए दरों का संशोधन विचाराधीन है और उसे बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया हुआ है। बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित हो जाने के पश्चात उसे शीघ्र ही प्राधिकरण को भेज दिया जाएगा। केपीटी ने मौजूदा दरों के लागू रहने की अवधि अगले 6 माह के लिए, 31 दिसंबर, **2015** तक बढ़ाने के लिए, इस प्राधिकरण से अनुरोध किया है और केपीटी के अनुसार ये संशोधित दरें पिछले प्रभाव से लागू होंगी।

5.1. पिछली बार, गांधीधाम नगर भूमि की मौजूदा संरचना दरों की वैधता बढ़ाने के अनुरोध के अंतर्गत केपीटी द्वारा अपने 31 दिसंबर 2014 के पत्र में उल्लेख किया गया था कि भूमि का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है और बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात प्रस्ताव, भेज दिया जाएगा। लेकिन, 31 मार्च 2015 तक प्रस्ताव हर हालत में भेजने के अनुरोध के बावजूद भी केपीटी ने अभी तक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। अब भी केपीटी ने अवधि बढ़ाने का अनुरोध करते समय अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने की समयावधि नहीं बतायी है। परंतु केपीटी ने उल्लेख किया है कि भूमि का मूल्यांकन कर लिया गया है और प्रस्ताव शीघ्र ही भेज दिया जाएगा। केपीटी द्वारा उल्लिखित उपर्युक्त स्थिति के आधार पर और यह मानते हुए कि इस संशोधन में विलंब हो गया है, पत्तन को निदेश दिए जाते हैं कि गांधीधाम नगर भूमि की संरचना दर में संशोधन का प्रस्ताव अधिकाधिक 31 दिसंबर, **2015** तक अवश्य प्रस्तुत करें।

5.2. केपीटी की गांधीधाम नगर भूमि की संरचना दरों की बढ़ी हुई वैधता अवधि 30 जून, **2015** को समाप्त हो गयी है। केपीटी द्वारा, केपीटी की गांधीधाम नगर भूमि की संरचना दरों की वैधता अवधि 31 दिसंबर, **2015** तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, केपीटी ने गांधीधाम नगर भूमि की संरचना दरों में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव अभी तक प्रस्तुत नहीं किया है। यहां तक कि यदि केपीटी अपना प्रस्ताव निर्धारित समय के अंदर पेश कर भी देता है तो भी प्राधिकरण द्वारा निर्णय लेने के लिए परामर्श प्रक्रिया पूरी करने समय लगेगा। इस परिप्रेक्ष्य में कि गांधीधाम नगर भूमि की संरचना दरों की वैधता अवधि 30 जून 2015 को समाप्त हो गयी है, यह प्राधिकरण, गांधीधाम नगर भूमि की मौजूदा संरचना दरों की वैधता अवधि इसके समाप्त होने की तिथि से 31 मार्च 2016 तक या केपीटी द्वारा प्रशुल्क प्रस्ताव के आधार पर संशोधित लीज़ किराया की अधिसूचना के प्रभावी होने की तिथि तक, जो भी पहले हो, गांधीधाम नगर भूमि की संरचना दरों की मौजूदा वैधता अवधि में बढ़ोत्तरी करता है।

5.3. इसके अलावा, सरकार द्वारा जारी 2010 के भू-नीति दिशानिर्देश (जिसके आधार पर गांधीधाम नगर भूमि की संरचना दरें अप्रैल 2012 में निर्धारित की गई थीं) में उल्लेख है कि इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित लीज़ किराया 2 प्रतिशत की दर से तब तक प्रति वर्ष बढ़ाया जाएगा जब तक लीज़ किराये को प्राधिकरण द्वारा संशोधित न कर दिया जाए। वर्ष 2012 में प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित आदेश में इस संबंध में विशेष शर्त भी दी गई हैं। यह शर्त पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी 2014 के भू-नीति निर्देशों में भी दी गई है। क्योंकि मौजूदा लीज़ किराया अनुसूची के अनुसार लीज़ किराया में उस समय तक तक के लिए पहले से ही 2 प्रतिशत की दर से वार्षिक बढ़ोत्तरी का प्रावधान किया गया है जब तक सक्षम अधिकारी द्वारा सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधित नहीं कर दिए जाते हैं और गांधीधाम नगर भूमि की संरचना दरों की विस्तारित अवधि के दौरान 2 प्रतिशत की दर से वार्षिक वृद्धि लागू रहेगी।

5.4. तथापि, इस संबंध में, यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि 2 प्रतिशत की दर से वार्षिक वृद्धि सहित मौजूदा लीज़ किराया की अवधि में बढ़ोत्तरी, वर्तमान परिदृश्य में आयी हुई समस्या का अस्थायी समाधान है। गांधीधाम नगर भूमि की संरचना दरों के लिए कांडला पत्तन न्यास (केपीटी) के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर निर्धारित किया जाने वाला लीज़ किराया पिछले प्रभाव से लागू किया जाना है, जैसा कि केपीटी ने अनुरोध किया है।

6. परिणामतः और उपर्युक्त दिए गए कारणों से यह प्राधिकरण, गांधीधाम नगर भूमि की मौजूदा संरचना दरों की वैधता अवधि, इसके पिछली समाप्ति की तिथि से 31 मार्च 2016, तक या केपीटी द्वारा प्रस्तावित प्रशुल्क के आधार पर संशोधित लीज़ किराया की अधिसूचना के प्रभावी होने की तिथि तक, जो भी पहले हो, बढ़ायी जाती है। केपीटी को निदेश दिए जाते हैं कि वह पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित भू-नीति दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए, केपीटी के गांधीधाम नगर भूमि की संरचना दरों में संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव, हर हालत में 31 दिसम्बर, 2015 तक अवश्य प्रस्तुत कर दे।

टी. एस. बालासुब्रमणियन, सदस्य (वित्त)
[विज्ञापन III/4/असा./143/15/319]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION

Mumbai, the 22nd December 2015

No. TAMP/20/2010-KPT.—In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of rate structure for Gandhidham Township land of KPT as in the Order appended hereto.

Tariff Authority For Major Ports

Case No. TAMP/20/2010-KPT

Kandla Port Trust

- - -

Applicant

ORDER

(Passed on this 7th day of December 2015)

This case relates to a proposal filed by Kandla Port Trust (KPT) for extension of the validity of the rate structure for Gandhidham Township Lands of KPT.

2. The lease rental for the Gandhidham Township Land of Kandla Port Trust (KPT) was last revised by this Authority on 9 April 2012. The lease rental revised by the Authority were implementable with retrospective effect from 1 January 2009 and valid for a period of five years, i.e. up to 31 December 2013. Thereafter, this Authority has extended the validity of the existing rate structure for Gandhidham Township Land of KPT from time to time.

3. The existing rate structure for Gandhidham Township Land of KPT was last extended based on the request of KPT by this Authority vide its Order No. TAMP/20/2010-KPT dated 13 February 2015 from the date of expiry till 30 June 2015 or till the date of effect of notification of the revised rentals based on the tariff proposal to be filed by the KPT, whichever is earlier. While extending the validity, the KPT was directed to file its proposal for revision of rate structure for Gandhidham Township Land positively by 31 March 2015.

4. Now, the KPT, vide its letter dated 20 November 2015 has stated that its proposal for revision of rates for Gandhidham Township Land is under consideration and has been submitted to the Board for its approval of Board. After the approval of the Board to the revised proposal same shall be sent shortly. In view of this position, the KPT has

requested this Authority to allow it to continue to charge at the existing rates for a further period of 6 months i.e. upto 31 December 2015, subject to condition that revised rates will be made applicable with retrospective effect.

5.1. The KPT while seeking extension of the validity of the existing rate structure of the Gandhidham township land on the last occasion vide its letter dated 31 December 2014 had stated that land valuation is completed and the proposal will be sent after seeking Board approval. The KPT has, however, not filed its proposal so far despite specific request to file its proposal by 31 March 2015 positively. Even now, while requesting for extension the KPT has not indicated the time frame within which it will file its proposal. The KPT has, however, reported that land valuation has been completed and that the proposal will be sent shortly after seeking Board approval. Based on the above status indicated by the KPT and also recognising that the revision is overdue the port is directed to file its proposal for revision of the rate structure for Gandhidham Township Land of KPT latest by 31 December 2015.

5.2. The extended validity of the existing rate structure for Gandhidham Township Land of KPT has expired on 30 June 2015. The KPT has requested to extend the validity of the rate structure for Gandhidham Township land till 31 December 2015. As mentioned above, the KPT has so far not filed its proposal for revision of the Gandhidham township land. Even if the KPT files its proposal within stipulated time, it will take time for the consultation process to conclude before final consideration of this Authority. In view of that and as the validity of the rate structure for Gandhidham Township Land of KPT has expired on 30 June 2015, this Authority extends the validity of the existing rate structure of the Gandhidham township land from the date of its expiry till 31 March 2016 or till the date of effect of notification of the revised lease rentals based on the tariff proposal to be filed by the KPT, whichever is earlier.

5.3. Further, the Land Policy Guidelines of 2010 issued by the Government (based on which the rate structure for Gandhidham Township Land has been fixed in April 2012) stipulates that the lease rentals approved by this Authority shall be escalated by 2% per annum till they are revised by the Authority. The Order approved by this Authority in April 2012 also prescribes a specific condition in this regard. This condition also prevails in the revised Land Policy Guidelines 2014 issued by the Ministry of Shipping. Since, the existing Schedule of lease rent already prescribes annual escalation @ 2% in the lease rentals till such time the rates are revised by the competent Authority and in line with the guidelines issued by the Government, the annual escalation @ 2% will continue to apply during the extended validity period of the rate structure for Gandhidham Township Land.

5.4. However, in this regard, it is relevant to mention here that the extension of the existing lease rentals with an annual escalation of 2% is only a provisional arrangement to avoid a vacuum in the current scenario. The lease rentals to be fixed for the Gandhidham township based on a proposal to be filed by the KPT in this regard may have to be given retrospective effect, as requested by the KPT.

6. In the result, and for the reasons given above, this Authority extends the validity of the existing rate structure for Gandhidham Township Land from the date of its expiry till 31 March 2016 or date of effect of notification of the revised lease rentals based on the tariff proposal filed by the KPT, whichever is earlier. The KPT is directed to file its proposal for revision of rate structure for Gandhidham Township Land of KPT positively by 31 December 2015 following the revised Land policy Guidelines, 2014 issued by the Ministry of Shipping.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[AdVT. III/4/Exty./143/15/319]